शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
राष्ट्रीय छात्रशक्ति

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 1 ■ अंक 8 ■ जनवरी 2018 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 32

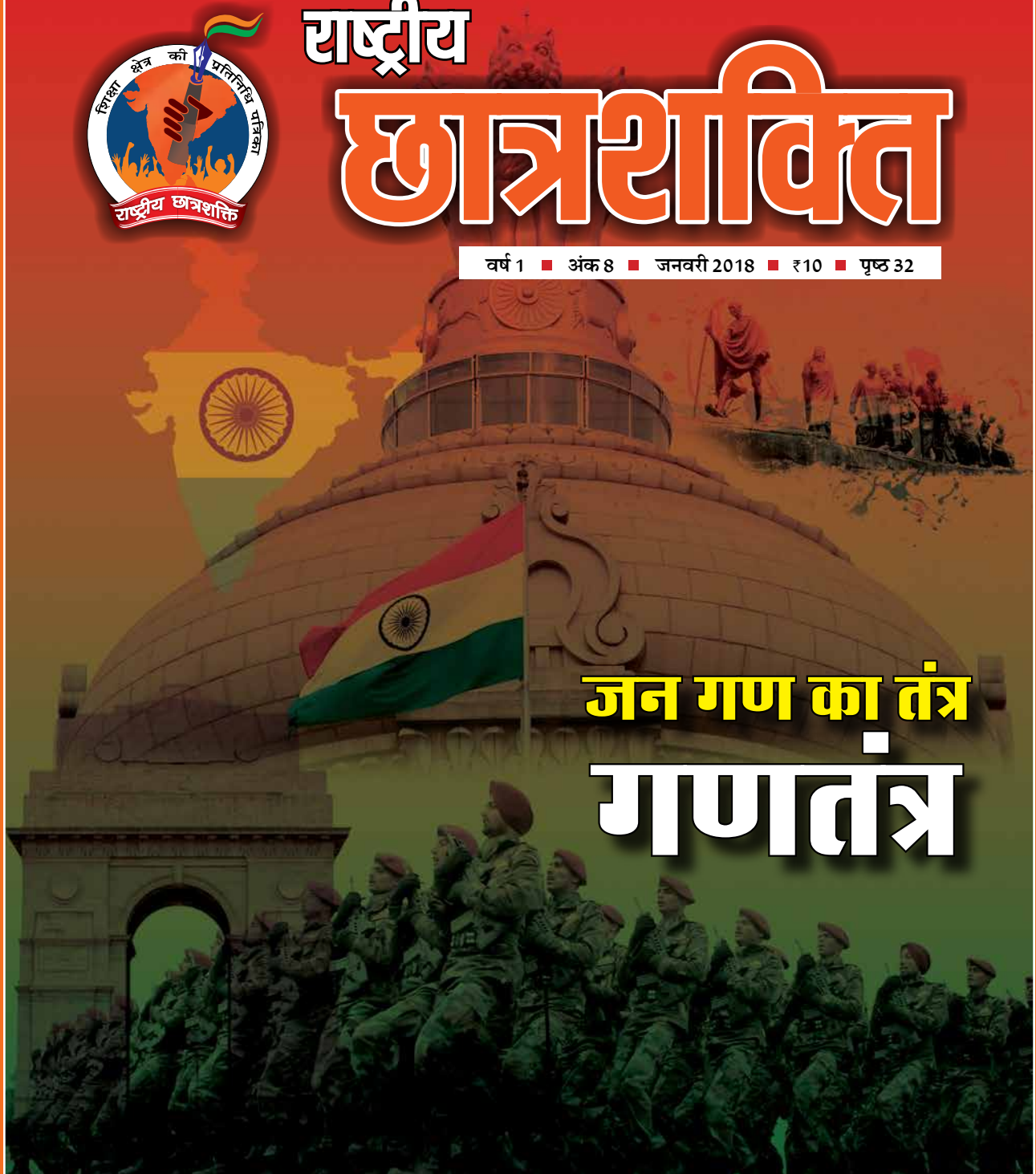

जन गण का तंत्र
गणतंत्र

भारतीय नवजागरण के अग्रदूत : स्वामी विवेकानंद 08

Using Kulbhushan Jadhav as a Ruse 19

निष्पक्षता ही पत्रकारिता की पहचान : प्रभु चावला 28

परिषद् गतिविधियाँ

असम छात्र नेता कार्यशाला को संबोधित करते क्षेत्रीय संगठन मंत्री नीरव घेलानी एवं सभागार में उपस्थित छात्र नेता

पश्चिम बंगाल में बढ़ रही महिला हिंसा के खिलाफ कैंडिल मार्च निकालकर प्रदर्शन करते अभाविप कार्यकर्ता

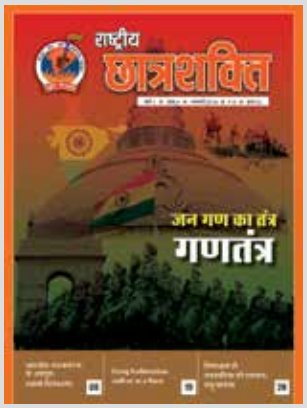

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 1, अंक 8
जनवरी, 2018

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित।

इस अंक में

05 **नए संकल्प लेने का दिवस बने गणतंत्र दिवस**
भारत आज विश्व की सबसे अधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दुनिया के देश भारत को पहले एक बड़ा बाजार समझते थे...

संपादकीय	04
जन गण मन का तंत्र	07
भारतीय नवजागरण के अग्रदूत : स्वामी विवेकानंद	08
ऊर्जा संरक्षण विषय पर एसएफडी की संगोष्ठी	10
राष्ट्रीय कला मंच द्वारा 'मंडाण' कार्यक्रम का आयोजन	11
तलाक पीड़ित महिलाओं का अधिकार है या नहीं?	12
छात्रसंघ चुनाव	14
Using Kulbhushan Jadhav as a Ruse	19
असम: अभाविप द्वारा छात्र नेता कार्यशाला आयोजित	21
Analysis India's vote in UN favour of Palestine	22
छत्तीसगढ़ अभाविप द्वारा प्रांत छात्रा अभ्यास वर्ग आयोजित	24
बंगाल में बढ़ती महिला हिंसा के खिलाफ अभाविप का प्रदर्शन	25
विद्या ददाति विनयम्	26
निष्पक्षता ही पत्रकारिता की पहचान : प्रभु चावला	28
नई शिक्षा नीति में और कितनी देर–परिचर्चा	29

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

भारत में सत्ता समाज-सेवा का माध्यम रही है। राजशाही के दौर में भी कुछ अपवादों को छोड़ दें तो लोक-कल्याण उसकी प्राथमिकता रही है। महात्मा गाँधी, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कभी आजादी की लड़ाई लड़ी थी, की कल्पना के स्वतंत्र भारत का आदर्श रामराज्य ही था।

कालान्तर में कांग्रेस और उससे निकले लोगों द्वारा बनाये गये राजनैतिक दलों ने येन-केन-प्रकारेण सत्ता प्रप्ति को अपना उद्देश्य बना लिया। सत्ता अकूत धन और शक्ति का स्रोत बन गयी। इसके चलते सदैव सत्ता में बने रहने की ललक पैदा हुई । मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता कर भी जब सत्ता में बना रहना असंभव हो गया तो पराजित पक्ष ने देश और समाज को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ हाथ मिलाने में भी संकोच नहीं किया। हाँ, इसे विचारधारा का आवरण पहनाने की कोशिश जरूर की।

2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद आयी मोदी सरकार के सामने भी चुनौती उत्पन्न करने के लिये ऐसे तमाम प्रयास सामने आये जिनमें निहित स्वार्थ पूरा करने के लिये अथवा चुनावी जीत हासिल करने के लिये राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सदभाव की बलि चढ़ाने की कोशिश हुईं। हाल ही में महाराष्ट्र में हुए दलित-मराठा संघर्ष के पीछे भी इन्हीं शक्तियों का हाथ नजर आता है।

दो सौ साल पुराने युद्ध की स्मृति में आयोजित समारोह की वर्षों पुरानी परंपरा रही। लेकिन इसमें किसी एक पक्ष मं गुजरात से जिग्नेश का आना और साथ में जेएनयू के उमर खालिद की मौजूदगी किसी नये षड्यंत्र की ओर इशारा करती है। उमर खालिद न दलित हैं और न मराठा। फिर उनकी भूमिका इस संघर्ष में कहां आती है। जिसने उन्हें इसके लिये आमंत्रित किया उसकी पहचान कर उसके इरादों की पड़ताल होनी ही चाहिये।

उमर की वहां मौजूदगी महज संयोग नहीं थी, यह साबित करने के लिये अगले दिन की घटना काफी है जब मुंबई के विले पार्ले के भाई दास हॉल में दोबारा एक आयोजन कर मामले को गरमाने की कोशिश हुई। इस आयोजन में भी जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद के अतिरिक्त इलाहाबाद की छात्र नेता ऋचा सिंह और जेएनयू के प्रदीप नरवाल भी शामिल थे। इसके आयोजन में स्थानीय विधान परिषद सदस्य कपिल पाटिल भी शामिल थे जो हाल ही में जदयू में शामिल हुए हैं।

समूचा घटनाक्रम जेएनयू अथवा उस्मानिया विश्वविद्यालय की घटनाओं को दोहराता हुआ लगता है। यह तो जांच के बाद ही सामने आयेगा कि दलित अथवा मराठा समुदाय की ओर से इन लोगों को निमंत्रित किया गया था अथवा नहीं। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश विघातक शक्तियां ऐसे मौके की तलाश में हैं और अवसर पाते ही अपना दांव चल देने की फिराक में हैं।

विशेष रूप से छात्र-युवाओं को सावधान रहना होगा क्योंकि उनकी आड़ में ही ऐसे तत्व अपना दांव खेल सकते हैं। जहां देश के भीतर इस प्रकार के तत्व निरंतर सक्रिय हैं वहीं सीमा पर पकिस्तान और चीन की हरकतें बढ़ती ही जाती हैं। भीतर और बाहर की समस्त चुनौतियों का सामना देश के युवाओं को करना होगा। इसके लिये वैचारिक रूप से देश को तैयार करने का संकल्प लेने का अवसर है युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती, जिसे अभाविप युवा दिवस के रूप में मनाती है।

वसंत पंचमी व गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगलकामनाओं सहित।

आपका,
संपादक

नए संकल्प लेने का दिवस बने गणतंत्र दिवस

भारत आज विश्व की सबसे अधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दुनिया के देश भारत को पहले एक बड़ा बाजार समझते थे। आर्थिक उदारीकरण ने देश के इस बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया, विनिवेश और विमुद्रीकरण ने अवसर उत्पन्न किये। परिणामत: देश सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र बनकर रह गया।

। अभिषेक रंजन।

गणतंत्र दिवस, भारत का एक राष्ट्रीय उत्सव! एक ऐसा दिन जबभारत के गणतांत्रिक देश बनने और उस संविधान के लागू होने को याद करते है, जो इस विशाल देश को एकसूत्र में पिरोकर रखने और एकजुट हो आगे बढ़ने की राह दिखाता है। गणतंत्र दिवस महज हमें देश की सैन्यशक्ति, पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन देखने का ही अवसर नही देता बल्कि एक लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारी अब तक की यात्रा को जानने और भविष्य के चुनौतियों एवं अवसरों को समझने का मौका भी देता है।

1950 से अब तक की यात्रा को देखे तो जहाँ पचास के दशक में भारत सदियों की गुलामी के बाद उठ खड़ा होने की जद्दोजहद कर रहा था, वही आज विश्व पटल पर न केवल महत्वपूर्ण स्थान रखता है बल्कि एक वैश्विक नेता के नाते भी देश की पहचान बनी है। हाल के कुछ उदाहरणों से इसे भली भांति समझा जा सकता है। भला 11 दिसंबर 2014 को कौन भारतीय भूल सकता है, जब संयुक्त राष्ट्र में अन्तराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के भारत के प्रस्ताव को 177 देशों ने समर्थन दिया। यह अपने आप में एक अनोखी और अद्वितीय घटना थी, जब संयुक्त राष्ट्र के सामान्य सभा में इतनी अधिक संख्या में किसी प्रस्ताव पर इतने देशों ने सहमती जताई, सह-आयोजक बनने को वे तैयार हुए। यह भारत की वैश्विक ताकत का ही नजारा था। सर्जिकल

स्ट्राइक के बाद विश्व का भारत को मिला समर्थन उस पर मुहर भी लगाती है। बेहद सस्ती लेकिन सबसे प्रभावी मंगलयान का प्रक्षेपण भारत की स्वदेशी वैज्ञानिक तकनीक का वह गर्वित पल था, जहाँ देश ने दुनिया के सामने अपनी वैज्ञानिक ताकत का लोहा मनवाया। आज इसरो न केवल भारत बल्कि कई देशों के अंतरिक्ष में पहुचने के सपने को साकार करने का जरिया भी बना हुआ है जो भारत को एक सॉफ्टपॉवर के रूप में प्रस्थापित करता नजर आता है। बीते कुछ सालों में देश ने न केवल अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की बल्कि दुनियाभर में फैले भारतवंशियों को देश की प्रगति में हाथ बटाने और एक नए भारत के निर्माण में सहयोगी बनाने की भी कोशिशें की है। यही वजह है कि विश्व के देशों में भारतवंशियों की प्रतिष्ठा न केवल बढ़ी है बल्कि वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति भी प्राप्त करने में सफल हुए है। विगत दिनों अमेरिका हो या

ब्रिटेन, कई देशों के आम चुनावों में भी इसकी छाप सहज महसूस की गयी।

भारत आज विश्व की सबसे अधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दुनिया के देश भारत को पहले एक बड़ा बाजार समझते थे। आर्थिक उदारीकरण ने देश के इस बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया, विनिवेश और विमुद्रीकरण ने अवसर उत्पन्न किये। परिणामतः देश सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र बनकर रह गया। देश के बदले नेतृत्व ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाने का संकल्प ले मेक इन इंडिया का स्वप्न देखा। आज परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही है। देश के युवाओं को रोजगार मिले, यह स्वप्न एक लम्बे समय से हकीक़त का रूप नही ले सका। सभी ने सरकारी नौकरी को ही रोजगार माना, देश की ताकत स्व-रोजगार और यहाँ के युवाओं की नवाचारी प्रवृति को अनदेखा किया। आज देश ने स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों के साथ स्व-सशक्तिकरण के रास्ते खोले, युवाओं को मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के जरिये स्वयं के बल खड़ा होने का अवसर दिया। स्वच्छता का मसला हो अथवा सामाजिक विकास के अवसर मुहैया कराने का, देश ने विगत वर्षों में एक बेहद रचनात्मक परिवर्तन होते देखा है। राजनीतिक प्रक्रियाओं में युवाओं के बढ़ते हस्तक्षेप ने जहाँ पारदर्शिता और राजनीतिक शुचिता के बहस को आगे बढ़ाने का काम किया, वही देश में आर्थिक पारदर्शिता के प्रयासों को भी उसने सराहा। सामरिक शक्ति बढ़ाने की हो या फिर सामाजिक बुराईयों को लेकर जन-जागरूकता,गणतंत्र को मजबूत करने के सभी प्रयासों ने देश को आगे बढ़ने की दिशा दी। संविधान के मूल्यों के अनुरूप समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा का लक्ष्य लेकर किये कई प्रयासों ने इसे बल प्रदान किया।

इन सबके बावजूद आज भारत कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। एक तरफ जहाँ हम वैज्ञानिक प्रगति के मामले में, आर्थिक उन्नति के आंकड़ों में दुनिया के सामने नजीर पेश कर रहे है, खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष तक, भारतीय प्रतिभा हमें गौरवान्वित होने का अवसर दे रही है, वही देश का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जब ग़रीबी की जिन्दगी जीने को अभिशप्त और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत दिखाई देता है तो 'हमें बहुत कुछ करना बाकी है' का एहसास होता है। हम विश्व शांति के प्रयासों में जुटे है, वही देश का अहित चाहने वाली ताकतों द्वारा अंजाम दी जा रही सामाजिक टकराव की घटनाएं और आंतरिक सुरक्षा के सामने खड़े प्रश्न देश के हर संवेदनशील मन-मष्तिष्क को बेचैन करते है और प्रतिप्रश्न करते है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? एक तरफ जहाँ दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली देश अमेरिका आज भी एक महिला को राष्ट्राध्यक्ष की जिम्मेवारी नही दे सका है, वही भारत के सर्वोच्च पदों को न केवल महिलाओं ने सुशोभित किया बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रति देश के जन-मन के सम्मान की वो सर्वोच्च अभिव्यक्ति भी बनी। अफ़सोस आज उसी भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति दिखाई पड़ती है। विश्व गुरु भारत के प्रबुद्ध मेधावी नागरिक पुरे दुनिया के कोने-कोने में बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं देकर भारतीय प्रतिभा का परिचय दे रहे है वही आज भी देश की आबादी का एक हिस्सा प्राथमिक शिक्षा से वंचित दिखाई देता है। इन विरोधाभासों के बीच देश आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति लिए प्रयासरत है।

आज आवश्यकता है कि हम इन परिस्थितियों में सकारात्मक चिंतन लिए कार्य करें। देश की युवाशक्ति भारत को स्वाभिमानी बनाने का संकल्प लिए कार्य करने का संकल्प ले तो कुछ भी असंभव नही। अगर विजय भाटकर यह जानकर शांत बैठ जाते कि अमेरिका सुपर कंप्यूटर बनाने की तकनीक साझा नही कर रहा है तो भारत कभी भी परम कंप्यूटर नही हासिल कर पाता। युवा कलाम एक बार मिली असफलता से चिंतित होकर स्वयं को अलग कर लेते तो भारत के पास आणविक क्षमता समय रहते नही हासिल होती। युवा नरेंद्र अपनी परेशानियों के साये तले जीवन जीना मंजूर कर लेता तो देश को दिशाबोध कराने वाला एक नायक नही मिलता। इसलिए भारत को आज आवश्यकता है उन युवाओं की जो देश की बेहतरी के संकल्प देखते है। छोटी-छोटी ख्वाईशों को छोड़कर, अपने सिमित दायरों को लांघकर देशहित में कुछ स्वप्न देखते है और उन्हें पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते है। आजभले देश में हजारों समस्याएं हो, अगर देश के युवा यह ठान लें कि हमें मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूँढना है, उसके समाधान हेतु प्रयास करना है तो स्थितियां बदलेगी। गणतंत्र दिवस का यह अवसर कुछ वैसे संकल्प लेने का है, जो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने और किसी समस्या या भावी चुनौती के समाधान का रास्ता दिखाए।यदि हम मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर भारत बनाने का स्वप्न अवश्य पूरा होगा, जो देश की प्राचीन वैभवशाली बुनियाद पर एक भव्य भारत बनाने का कार्य करेगी, जहाँ लोग विश्व शांति और कल्याण हेतु संकल्पबद्ध होंगे, देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति में हाथ बंटाते दिखेंगे। ■

जन गण मन का तंत्र

। अवनीश राजपूत।

राष्ट्र केवल एक भूमि के टुकड़े का नाम नहीं हो सकता। कोई एक भूखंड और उस पर बसने वाला समाज मिलकर अपने आप में राष्ट्र नहीं बन जाते। निश्चित भूमि, उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाला समाज और उन्हें एकात्म बनाने वाली सांझी सांस्कृतिक धारा मिल कर एक राष्ट्र का निर्माण करती है। भारत राष्ट्र दिखने वाली अनेक प्रकार की विविधताओं के बाद भी एक राष्ट्र है। हजारों वर्षों में हमने सैंकड़ों बाहरि आक्रमण झेले हैं। हमारा इतिहास चुनौतीपूर्ण रहा है। शक, हूण, कुषाण, अरब, तुर्क, मुगलों और फिर अंग्रेजों आदि आक्रांताओं से हमारे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को चुनौती मिलती रही है। लेकिन आज भी हमारा राष्ट्र एक है, हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडित है। यदि हम इस प्रश्न का उत्तर ढूढ़ने का प्रयास करेंगे कि क्रूर आक्रांताओ के क्रूर प्रहारों के बाद भी भारतीय एकात्मता अडिग क्यूं है तो उसका उत्तर सिर्फ हमारी संस्कृति में निहित है, जो हमें एक बनाये रखती है। हजारों वर्षों से भारत में कोई व्यक्ति कहीं भी जन्मा हो, रहा हो या फिर कहीं भी काम कर रहा हो, उसमें एकात्मता का भाव जगाने का कार्य इस पावन धरा पर जन्में महापुरुषों ने किया है। भारतवासियों को अपनी इस विरासत पर गर्व होना चाहिए, और यह हुंकार भरने में भी संकोच नहीं होना चाहिए कि हम दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीयता के वारिस हैं।

अनेक लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि जिस सनातन राष्ट्रीय धारा का वर्णन यहां किया जा रहा है उसके प्रमाण क्या हैं? प्रमाण चाहिये तो सीधे रामायण के युग में लौट चलिए। अगर अयोध्या से लेकर रामेश्वरम् तक एक ही सांस्कृतिक धारा नहीं बह रही थी तो उत्तर में कौशल प्रदेश के राजकुमारों की अगुआई में सुदूर दक्षिण तक आतंक का पर्याय बनी ताकतों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष नजर नहीं आता। अगर भारत एक राष्ट्र नहीं होता और देश के सुधिजनों को इसकी समग्र चिंता नहीं होती तो वर्तमान बिहार में जन्मे विष्णुगुप्त चाणक्य देश के उत्तर पश्चिम में सिकंदर के हमले के खिलाफ चन्द्रगुप्त की अगुआई में प्रतिरोध की दीवार नहीं खड़ी करते। हमारे संत-महात्मा वैदिक काल से ही इस राष्ट्रीय इकाई के सर्वांगीण पोषण की चिंता करते रहे हैं। दक्षिण में केरल की धरती पर जन्मे शंकराचार्य ने चार धामों की स्थापना के लिए इस सनातन राष्ट्र के चार कोनों को चुना उत्तर में बद्रीनाथ की स्थापना की तो पूर्व में जगन्नाथ पुरी, दक्षिण में रामेश्वरम्, पश्चिम में द्वारका की स्थापना की। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म भले ही केरल में हुआ, लेकिन उनके मन में कल्पना सम्पूर्ण भारत वर्ष की थी। महापुरुष देश के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गए तो उनके मन में केवल एक भारत की कल्पना ही थी, यह सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना छत्रपति शिवाजी से लेकर गुरु गोबिन्द सिंह जी के समय में भी दिखाई देती है। सिख गुरुओ की वाणी संकलन हेतु जब आदि गुरु ग्रन्थ साहिब का प्रकाश किया गया तो उसमें देश के हर क्षेत्र के हर जाति के संतो की वाणी को सम्मिलित किया गया।

यही कारण है कि जब आनंदपुर साहिब में दशमेश पिता

ने एक के बाद एक पांच शिष्यों से सिर मांग लिए तो उनमें द्वारका से लेकर लाहौर, हस्तिनापुर, बीदर और ओडिशा के जगननाथपुरी तक के और विभिन्न जतियों से संबंध रखने वाले पांच प्यारे उठ खड़े हुए। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन आदि मोक्षदायक पुरियां जिनमें देश के प्रत्येक क्षेत्र से लोग आकर अपने को धन्य मानते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा सिंधु कावेरी आदि नदियों का मां के रूप में पूजन और उनमें स्नान से पुण्य की कल्पना। समान शाश्वत जीवन मूल्य समान शत्रु-मित्र भाव जिसे किसी भी भाषाए बोली आस्था और जीवनशैली वाला भारतीय अपनाता है। वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्र ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ही अपना मानने का मार्ग प्रशस्त किया। ■

भारतीय नवजागरण के अग्रदूतः स्वामी विवेकानंद

।संजीव कुमार सिन्हा।

भारतीय नवजागरण का अग्रदूत यदि स्वामी विवेकानेद को कहा जाय, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने सदियों की गुलामी में जकड़े भारतवासी को मुक्ति का रास्ता सुझाया। जन-जन के मन में भारतीय होने के गर्व का बोध कराया। उन्होंने मानव समाज को अन्याय, शोषण और कुरीतियों के खिलाफ उठ खड़े होने का साहस प्रदान किया और पाश्चात्य संस्कृति की चकाचैंध में दिशाभ्रमित भारतीय नौजवानों के मन-मस्तिष्क में स्वदेश-प्रेम एवं हिन्दुत्व-जीवन दर्शन के प्रति अगाध विश्वास पैदा किया। अपनी विद्वतापूर्ण एवं तर्क आधारित भाषण से दुनिया भर के बुद्धिजीवियों के बीच भारत के प्रति एक जिज्ञासा पैदा की। भारत की एक अनोखे ढंग से व्याख्या की। उन्होंने भारतीय बौद्धिक क्रांति का सूत्रपात किया। स्वामी विवेकानंद ने उद्घोष किया कि समस्त संसार हमारी मातृभूमि का ऋणी है। स्वामीजी ने अध्यात्म को अंधविश्वास एवं कालबाह्य हो चुके कर्मकांड से मुक्त कराया एवं हिन्दुत्व की युगानुकूल व्याख्या की तथा अध्यात्म को मानव के सर्वांगीण विकास का केन्द्र-बिन्दु बताया।

भारतवर्ष में 'गुरू-शिष्य' की अभिनव परंपरा रही है। हम सब जानते है कि छत्रपति शिवाजी, सम्राट चन्द्रगुप्त, प्रभु श्री रामचन्द्र जैसे कर्मशील एवं प्रतापी योद्धाओं के निर्माण और सफलता के पीछे समर्थ गुरू रामदास, चाणक्य, विश्वामित्र जैसे गुरूजनों का स्नेह और आशीर्वाद का अप्रतिम योगदान रहा है। ठीक इसी प्रकार कलकाा के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस के स्नेहिल सान्निध्य और आशीर्वाद से स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति एवं हिन्दू धर्म का प्रचार करके संसार का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया।

स्वामीजी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। वे स्वदेश-प्रेम को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इसलिए भारत की स्वाधीनता के लिए निरंतर युवा-वर्ग को अपने बौद्धिक आख्यायनों से जगाते रहे। उनकी रचनाओं को पढ़कर नवयुवकों में स्वाधीनता प्राप्त करने की तीव्र प्रेरणा जागृत हुई। क्रांतिकारियों के बीच वे सर्वमान्य आदर्श रहे। उनके जीवन कर्म से प्रभावित होकर अनेक क्रांतिकारी, अंग्रेजों के अत्याचार से क्रुद्ध हो उनकी हत्या कर देते तथा हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूम लेते। स्वामीजी ने कहा-'आगामी पचास वर्षों के लिए हमारा केवल एक ही विचार-केन्द्र होगा और वह है हमारी महान मातृभूमि भारत। दूसरे सब व्यर्थ के देवताओं को कुछ समय तक के लिए हमारे मन से लुप्त हो जाने दो। हमारी जाति-स्वरूप केवल यही एक देवता है जो जाग रहा है। जिसके हर जगह हाथ है, हर जगह पैर है, हर जगह कान है, जो सब वस्तुओं में व्याप्त है। दूसरे सब देवता सो रहे है। हम क्यों इन व्यर्थ के देवताओं के पीछे दौड़े और उस देवता की, उस विराट की, पूजा क्यों न करे जिसे हम अपने चारों ओर देख रहे है। जब हम उसकी पूजा कर लेंगे तभी हम सभी देवताओं की पूजा करने योग्य बनेंगे।''

स्वामी विवेकानंद के जीवन में शिकागो धर्म सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस सत्रह दिन के धर्म सम्मेलन ने इस तीस वर्षीय हिन्दू संन्यासी को जगत में सुविख्यात कर दिया। 11 सितंबर, 1893 से प्रारंभ हुए इस सम्मेलन में उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। भाषण प्रारंभ करते हुए जैसे ही उनके मधुर कंठ से 'अमरीकी निवासी बहनों और भाइयों' संबोधन निकला, सभा भवन काफी देर तक तालियों से गूंजता रहा। वहां उपस्थित हजारों प्रतिनिधि इस आत्मीय संबोधन को सुनकर अभिभूत हो गए। स्वामीजी ने आगे कहा-'मुझको ऐसे धमार्वलंबी होने का गौरव है, जिसने संसार को 'सहिष्णुता' तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय दिया। सांप्रदायिकता, संकीर्णता और इनसे उत्पन्न भयंकर धार्मिक उन्माद हमारी इस पृथ्वी पर काफी समय तक राज कर चुके है। इनके घोर

अत्याचार से पृथ्वी थक गई है। इस उन्माद ने अनेक बार मानव रक्त से पृथ्वी को सींचा है, सभ्यताएं नष्ट कर डाली है तथा समस्त जातियों को हताश कर डाला है। यदि यह सब न होता तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका भी समय आ गया है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो घंटे आज इस सभा के सम्मान के लिए बजाए गए, वे समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किए जाने वाले समस्त अत्याचारों तथा मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्युनाद सिद्ध होंगे।'

आज समाज-जीवन में जो विकृतियां पनप रही है, उसके बारे में उन्होंने काफी पहले सावधान कर दिया था। आज यह सहज ही देखने को मिल रहा है कि विश्वविद्यालय परिसरों में ड्रग-ड्रिंक-डिस्को की कचरा संस्कृति में सराबोर आज का युवक स्व-विस्मृति के कगार पर है। उन्होंने पाश्चात्य जीवन शैली के अंधानुकरण को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा था, 'ऐ भारत! यही तेरे लिए एक भयानक खतरे की बात है-तुम्हें पाश्चात्य जातियों की नकल करने की इच्छा ऐसी प्रबल होती जा रही है कि भले-बुरे का निश्चय अब विचार-बुद्धि, शास्त्र या हिताहित ज्ञान से नहीं किया जाता। गोरे लोग जिस भाव और आचार की प्रशंसा करे या जिसे न चाहे, वही अच्छा है और वे जिसकी निंदा करे तथा जिसे न चाहे, वही बुरा! खेद है, इससे बढ़कर मूर्खता का परिचय भला और क्या होगा? यह कथन आज भी प्रासंगिक लगता है।

स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों पर अपना ध्यान तो रखते ही थे साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भी होने वाले सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों का अध्ययन और विचार करते थे। उन दिनों समाजवाद के विचार बड़ी तेजी से फैल रहे थे। उनका मानना था कि 'भारत को समाजवाद-विषयक अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने से पहले यह आवश्यक है कि उसमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए। सर्वप्रथम हमारे उपनिषदों, पुराणों और अन्य सब शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य निहित है, उन्हें इन सब ग्रंथों के पृष्ठों के बाहर लाकर, मठों की चारदीवारियां भेदकर, वनों की नीरवता से दूर लाकर, कुछ संप्रदाय-विशेषों के हाथों से छीनकर देश में सर्वत्र बिखेर देना होगा, ताकि ये सत्य दावानल के समान सारे देश को चारों ओर से लपेट लें- उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सब जगह फैल जाए- हिमालय से कन्याकुमारी और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक सर्वत्र वे धधक उठें।'

स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों व रचनाओं से जन-जन में प्रबल इच्छाशक्ति व स्वाभिमान तो जगाया ही, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य को पाने में एक सुदृढ़ संगठन की आवश्यकता हुई। वे 'संघे शक्ति कलौयुगे' के सूत्र की महता को भलीभांति जानते थे। वे चाहते थे कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में आम जन भी हाथ बंटाये। 1 मई, 1897 के दिन उन्होंने स्वामी रामकृष्ण देव के कुछ शिष्यों के सम्मुख एक योजना रखी। उन्होंने कहा कि 'विश्व के कई देशों का भ्रमण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि हमें पवित्र धर्म एवं गुरूदेव के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सुदृढ़ संगठन बनाना ही होगा।' आज सर्वविदित है कि देश के कोने-कोने में 'रामकृष्ण मिशन' द्वारा संचालित सैकड़ों अस्पताल, विद्यालय व सेवाकार्य राष्ट्र के नवोन्मेष व परम वैभव प्राप्त करने की दृष्टि से अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।

स्वामीजी ने मात्र 39 वर्ष की आयु में ही अपना भौतिक देह त्याग दिया और इतनी कम उम्र में ही अनथक प्रवास करते हुए एक बेहतर भारत व विश्व के निर्माण के लिए निरंतर सक्रिय रहे। अपने जीवन का क्षण-क्षण मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने सशक्त और समृद्धिशाली भारत का जो सपना देखा, उसे आज भी अनेक राष्ट्रवादी संस्थाएं पूरा करने में जुटी हुई हैं। ऐसे वक्तृत्व व कर्तृत्व के धनी एवं तेजस्विता के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जन-जन के आदर्श पुरूष है। उनका संपूर्ण जीवन-कर्म व विचार हम सबके लिए पाथेय है। ■

ऊर्जा संरक्षण विषय पर एसएफडी ने आयोजित की संगोष्ठी

वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतों के विकास पर सरकार को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ऊर्जा की कमी दूर करने में हम सभी अपना योगदान अपनी आदतों में बदलाव लाकर दे सकते हैं। इसका दुरूपयोग रोककर हम अपना योगदान पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं। ये बातें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निराला आर्ट गैलेरी में प्लाज्मा वैज्ञानिक डॉ. चन्द्रभूषण द्विवेदी ने कहीं। बता दें कि डॉ. द्विवेदी विश्व श्रेष्ठ 100 वैज्ञानिकों की सूचि में शामिल हैं। वे विकासार्थ विद्यार्थी (एसएफडी) के तत्वाधान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसका विषय भारत में ऊर्जा संरक्षण : चुनौतियां व संभावनाएं रखा गया था। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण की चुनौतियां पर प्रकाश डालते हुए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर, नाभिकीय ऊर्जा के विकास पर जोर देने की बात कहीं।

सेवानिवृत आईएएस व मुख्य अतिथि श्री बी के सिंह ने दैनिक जीवन में उर्जा संरक्षण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने बताया कि ऊर्जा का संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है। जबकि विशिष्ट अतिथि मनीष देव शांडिल्य ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को दैनिक जीवन में बिजली व पेट्रोल की खपत कम करने करने की सलाह दी। अभियंता शिवब्रत राय ने स्टार रेटिंग उपकरणों के विषय में जानकारी प्रदान की।

एसएफडी के प्रांत संयोजक विकास पाण्डेय ने वर्ष भर में एसएफडी द्वारा उर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने उर्जा संरक्षण को संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों में शामिल करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में प्राध्यापक डॉ संजय कुमार द्विवेदी, पंकज पाण्डेय, श्याम प्रकाश पाण्डेय, अश्वनी मौर्या, मयंक मिश्रा, भूमेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे थे। ■

राष्ट्रीय कला मंच द्वारा 'मंडाण' कार्यक्रम का आयोजन

उत्तराखंड राष्ट्रीय कला मंच की ओर से मंडाण सांस्कृतिक कला उत्सव में छात्रों ने पर्वतीय अंचलों की सांस्कृतिक बनावटों को जाना। यमुना कॉलोनी, देहरादून में आयोजित इस सांस्कृतिक उत्सव में उत्तराखंड के नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पढ़ाई के अतिरिक्त छात्रों का उद्देश्य मात्र चुनाव तक सीमित न रह कर सांस्कृतिक गतिविधियों में भी होना चाहिये। संस्कृति बचाने के लिये अभाविप ने सकारात्मक प्रयास किये है। आज जितनी तेजी से हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उस हिसाब से अभाविप जैसे संगठन के लिए चुनौतियां और बढ़ी है।

राष्ट्रीय कला मंच के संयोजक सौरभ उनियाल ने कहा कि हमें अपने मूल्यों को समझना पड़ेगा, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को समझे बगैर राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं है। राष्ट्रीय कला मंच अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि कला एवं संस्कृति के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना हमारा मूल उद्देश्य है। वहीं क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज निखरा ने अपने संबोधन में कहा कि अभाविप केवल छात्र संघ चुनाव तक सीमित नहीं है, विद्यार्थी परिषद् समाज क्षेत्र में कार्य करता है और राष्ट्रीय कला मंच जैसे प्रकल्पों के माध्यम से सांस्कृतिक चेतना को जगाने का काम करती है।

इस अवसर पर चित्रकला प्रदर्शनी, गायन प्रतियोगिता के साथ ही नाटक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन कवि सम्मेलन के दौरान कवियों ने अपनी कविताओं से हँसाया, वहीं दूसरी ओर पलायन का दर्द भी पेश किया। मौके पर अभाविप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. के शाही, प्रदेश संगठन मंत्री प्रदीप शेखावत समेत सैकड़ो कार्यकर्ता मौजूद रहे। ■

तलाक पीड़ित महिलाओं का अधिकार है या नहीं?

| अक्षय दूबे 'साथी' |

कोई भी प्रगतिशील समाज सुधार के लिए बड़ा स्थान बचाकर रखता है। पुरानी और अमानवीय परंपराओं को उखाड़ फेंकने से वह हिचकता नहीं है। समाज के भीतर से ही समाज बदलने की ध्वनियां स्पंदित होती है। कहीं यह चिंगारी अपनी आग से दकियानूसी सोच को जलाकर खाक कर देती है। तो कहीं रूढ़ीवादी खांचे को बनाए रखने के पैरोकार उस आवाज की चिंगारी को मसल कर रख देते हैं। भारत में मुस्लिम समाज आज इस दौर से गुजर रहा है। 21वीं सदी में जहां समानता की ओर कदम बढ़ रहे हैं वहीं धार्मिकता और परंपरा के नाम पर महिला विरोधी व्यवहारों को बनाए रखने के पक्ष में जोर भी लगाया जा रहा है। लेकिन जागरूक जनता के मन में सुधार को अंगीकार करने की बयार भी बखूबी बह रही है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत के निर्णय में मुस्लिम समाज में एक बार में तीन बार तलाक देने की प्रथा को निरस्त करते हुए अपनी व्यवस्था में इसे असंवैधानिक, गैरकानूनी और शून्य करार दिया। कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक की यह प्रथा कुरान के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने 365 पेज के फैसले में कहा, "3:2 के बहुमत से दर्ज की गई अलग-अलग राय के मद्देनजर 'तलाक-ए-बिद्दत' तीन तलाक को निरस्त किया जाता है।"

कोर्ट के इस फैसले का पूरे देश में स्वागत किया गया। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों के मन की निराशा भी जाहिर हुई। केन्द्र सरकार इस कुरीति के विरूद्ध कानून बनाने में पक्ष में खड़ी है तो वहीं कई विपक्षी दल और मुस्लिमों के कथित रहनुमां कानून नहीं बनने देने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं।

सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति से आखिरकार 28 दिसंबर को लोकसभा में ऐतिहासिक तीन तलाक बिल पास हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया। बिल पर जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर गरीब मुस्लिम समाज की महिलाओं के पक्ष में खड़ा रहना अपराध है तो हम इस अपराध को 10 बार करने को तैयार हैं।

लेकिन इस विधेयक के खिलाफ कुछ तरक्की पसंद नेताओं का बयान काफी चौंकाने वाला और हास्यास्पद भी लगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हर कोई महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में है। इस बिल को संसद की स्थायी समिति में भेजा जाना चाहिए। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल मौलिक अधिकारों का हनन करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, "ट्रिपल तलाक पर यह बिल मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है। सरकार को अभी यह बिल पास नहीं करना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सलाह मांगी जाए। यह बिल इस्लाम धर्म के खिलाफ बड़ी साजिश है।"

इन बयानों को चौंकाने वाला इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि भारत जैसे लोकतंत्र में लाखों मां-बहनों का जीवन सिर्फ तलाक...तलाक...तलाक शब्द के क्रूर प्रहार से एक झटके में बर्बाद हो जाता हो, औरतें किसी अदालत में गुहार भी नहीं लगा पा रही हों, ऐसे में उस प्रथा को सिर्फ वोट बैंक के खातिर बनाए रखने की वकालत करना क्या झंकझोरता नहीं है?

कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तलाक-ए-बिद्दत खुद-ब-खुद अवैध हो गया, ऐसे में कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

लेकिन इस फैसले के बाद भी अब तक तीन तलाक के तकरीबन 100 मामले सामने आ चुके हैं। क्या यह इन नेताओं की आंखे नहीं खोलता?

कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम समुदाय को यह खतरा बता रहे हैं कि यह बिल धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ करने वाला है। जबकि कानून मंत्री के शब्दों में, "यह कानून किसी पूजा, इबादत या मजहब से जुड़ा नहीं होगा बल्कि नारी सम्मान और गरिमा के लिए है। 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक', 2017 के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि तलाक-ए-बिद्दत के कारण असहाय विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लगातार उत्पीड़न का निवारण करने के लिये उन्हें जरूरी राहत प्रदान करने के वास्ते समुचित विधान की तुरंत आवश्यकता है।"

तीन तलाक पर कोर्ट का फैसला हो अथवा लोकसभा में बिल के पारित होने की बात हो दोनों ही मौकों पर मुस्लिम महिलाओं ने असली आजादी महसूस की होगी। लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण का लेखन जब होगा तब कुछ लोग इस सदी के दुश्मन के तौर पर दिखाई देंगे। इन कथित धार्मिक नेताओं से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की भाषा में यह सवाल है कि सदन को तय करना है कि तलाक की पीड़ित महिलाओं का अधिकार है अथवा नही? ■

प्रिय मित्रों!

शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का जनवरी, 2018 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, बसंत पंचमी, तीन तलाक जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें:-

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल 11 में से 9 पदों पर अभाविप का कब्जा

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने शानदार जीत हासिल की है। विश्वविद्यालयीन छात्र संघ चुनाव 2017-18 के कुल 11 पदों में से अभाविप ने 9 पदों पर जीत हासिल की है, जिसमें अध्यक्ष एवं पुस्तकालय मंत्री भी शामिल हैं।

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संपन्न छात्र संघ चुनाव में अभाविप के ब्रजेश कुमार त्रिपाठी बतौर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, वहीं पुस्तकालय मंत्री के रूप में अखिलधर चुने गये हैं। अगर संकाय प्रतिनिधि की बात करें तो संकाय प्रतिनिधि के सभी सात पदों पर अभाविप के प्रतिनिधियों ने एक तरफा जीत हासिल की है। संकाय प्रतिनिधि के रूप में पुष्पराज, बाशुदेव मिश्रा, श्याम बहादूर, मोहन कुमार तिवारी, अभिषेक चौबे एवं मोहित मिश्रा निर्वाचित हुए हैं। जीत के बाद अभाविप ने विजय जुलूस निकाला, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की खुशी जाहिर की। जीत के बात अभाविप नेताओं ने कहा कि यह जीत विद्यार्थी परिषद् के प्रति छात्रों के स्नेह को दर्शाता है। छात्र जानते हैं कि उनके हितों की बात करने वाला छात्र संगठन, विद्यार्थी परिषद् ही है। परिषद् एक मात्र ऐसा छात्र संगठन है जो साल के 365 दिन परिसर में सक्रिय रूप से छात्रों के लिए कार्य करता है। ■

कोल्हान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद् की अप्रत्याशित जीत

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने झारखंड छात्र मोर्चा के जबड़े से कोल्हान विश्वविद्यालय को छिन लिया है। कोल्हान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर भगवा लहराया है। अध्यक्ष समेत पांचो सीटों पर अभाविप एवं उनके समर्थकों की जीत हुई है। इस जीत ने जहां अभाविप के उत्साह को दोगुना कर दिया है वहीं जेसीएम को एक बार फिर हाशिये पर ला दिया है।

अभाविप नेताओं की मानें तो विश्वविद्यालय के छात्रों ने संकीर्ण राजनीति करने वाले संगठनों को नकार दिया है। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर को राजनीतिक अखाड़ा बनने से रोक दिया है। कुछ संगठनों ने चुनाव के दौरान बाहरी–भीतरी का हवा देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। बता दें कि परिणाम से पहले जेसीएम के नेता अपने जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन अभाविप की सटीक रणनीति ने सामने उनकी एक न चली और कोल्हान विश्वविद्यालय से जेसीएम का सूपड़ा साफ हो गया। कोल्हान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष के रूप में शत्रुघ्न मुंडा, उपाध्यक्ष किरण कुमार सुम्बरूई, सचिव सुबोध महाकुड़, उप सचिव वीरेन्द्र कुमार एवं संयुक्त सचिव के पद पर उत्तम कुमार निर्वाचित हुए हैं।

विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव मे विभिन्न पदों पर 19 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें सबसे अधिक सचिव पद पर 5 उम्मीदवार थे, जबकि अध्यक्ष व उप सचिव पदों के लिए चार-चार उम्मीदवार. वहीं संयुक्त सचिव व उपाध्यक्ष के पदों के लिए तीन-तीन उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि जीत के लिए प्रत्याशियों को 9 मत लाना जरूरी था। अभाविप एवं उनके समर्थित प्रत्याशियों ने बहुमत के आंकड़े को आसानी से छू लिया, वहीं उपाध्यक्ष पद का चुनाव सबसे रोचक रहा, चूंकि उपाध्यक्ष को कुल 16 में से 16 वोट मिले यानि विपक्षी प्रत्याशी भी वोट परिषद् के उम्मीदवार को दे गये। ■

प्रांतीय अधिवेशन

हिमाचल प्रदेश के प्रान्त अधिवेशन में राष्ट्रीय सह–संगठन मंत्री के. एन. रघुनंदन को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित करती प्रदेश मंत्री हेमा ठाकुर

हिमाचल प्रदेश के 38 वें प्रांतीय अधिवेशन के खुले अधिवेशन के दौरान अभाविप पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता

प्रांतीय अ

बिहार के 59वें प्रांतीय अधिवेशन में मंचासीन अतिथि एवं अभाविप पदाधिकारी

बिहार प्रांतीय अधिवेशन के दौरान निकाली गई भव्य शोभा यात्रा

अधिवेशन

गोरक्ष प्रान्त के 57 वें अधिवेशन में उद्बोधन देते अभाविप के अखिल भारतीय जनजाति कार्य प्रमुख व क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत

गोरक्ष प्रान्त अधिवेशन में शोभा यात्रा के दौरान अभाविप कार्यकर्ता

प्रांतीय अधिवेशन

राजस्थान के 53 वें प्रांतीय अधिवेशन के दौरान सभागार में उपस्थित अतिथिगण एवं अभाविप कार्यकर्ता

विदर्भ प्रांतीय अधिवेशन में शोभायात्रा के दौरान कार्यकर्ता

Using Kul Bhushan Jadhav as a Ruse

Swadesh Singh

The case of Kulbhushan Jadhav does not just pertain to violation of one man's rights, it is, infact, part of the larger picture - one that involves the rogue state named Pakistan and its nefarious designs against India.

It all began in 2016, when Pakistan arrested Indian businessman Kulbhushan Jadhav and termed him an 'Indian intelligence agent'. He was charged with being a part of many conspiracies and terrorist attacks in Pakistan. Jadhav was tried in a military court of Pakistan and summarily sentenced to death.

It has been proven time and again that Pakistan harbours terrorists, gives them training on its soil and uses them against India. The seeds of terrorism which Pakistan sowed years ago have come at great cost. The double-edged sword of terrorism has destabilised Pakistan and the country has no recourse but to blame India for its own poor choices. The Kulbhushan Jadhav Case is just another chapter in the long history of preposterous conspiracy theories which Pakistan builds now against India to draw attention away from its terminally ill polity.

It was once popular that Pakistan is run by Allah, Army and America. Not the elected government, but secret service and army are the real rulers of Pakistan. To remain perpetually relevant, they need a permanent enemy - India. Their strategy is to unite the fundamentalist forces in the name of Islam. Ironically, these fundamentalist forces have now made inroads into the life and breath of Pakistan. Many organisations have now cropped up in Pakistan who get support from the Arab world to spread a particular type of Islam. These fundamentalist, terrorist organisations have also formed their political outfits and are going to contest the coming elections. A few days back known terrorist Hafiz Saeed declared that his party will contest elections in the coming days.

Pakistan wants to blame India for these dangerously proliferating problems that have rendered Pakistan a failed state. Hence, the case in question is not just about Kulbhushan Jadhav - a former navy commander and now an businessman with a private life who was traveling to Iran for work - it is about the larger picture.

We also have the case of Sarabjeet Singh who was tortured and killed by Pakistani agencies. In similar cases, many Indians were abducted from Afghanistan, Iran and the Indian border and charged with terrorist conspiracy and brutally killed - all this without a chargesheet or a single document. All such cases were tried in military courts which is a violation of the international convention where civilians cannot be tried in military courts. It is pertinent to mention here that Kulbhushan Jadhav was not a serving navy commander but had retried from service and was travelling in his capacity as a businessman.

In the case of Jadhav, Pakistan created

a propaganda of arresting an Indian 'spy' involved in criminal conspiracy and responsible for the death of many in Balochistan. As many as 13 times, the Indian High Commissioner asked the Pakistani authorities to produce his papers and chargesheet filed in the military court. But to no avail. India has now accused Pakistan of violating the Vienna Convention by repeatedly denying consular access to Jadhav.

The present central government doggedly pursued the Jadhav case and brought it to the International Court of Justice. It was a symbolic win for India in May 2017 when the ICJ asked Pakistan to stay Jadhav's death penalty. Ordering the stay, ICJ Justice Ronny Abraham had directed Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif to "act in such a way so as to enable the court to enforce any decision it takes on the Indian plea." This effectively stayed Jadhav's execution until the court hears the matter and passes orders.

India had won a stay from the ICJ on Jadhav's execution on May 18 following Pakistan's refusal to allow consular access to the Indian High Commission in Islamabad despite repeated requests. No date has been fixed for the case to resume in the ICJ. Officials associated with the case said it would take at least weeks, before the ICJ takes up the Kulbhushan case.

Jadhav was sentenced to death by a military court while the Army Chief upheld his conviction. His mercy plea has been languishing for months before the Army Chief. Pakistani officials have said that there are still two forums of appeal left for Jadhav even if the Army Chief refuses his mercy plea.

To save its face, Pakistan invited Jadhav's family to meet him on 25 December 2017. But here again, they insulted his mother and wife and asked them to go without the 'mangalsutra' and shoes and forbade them from talking in their mother tongue. Minister of External Affairs, Sushma Swaraj, informed Parliament that Jadhav was shocked to see his mother without the 'mangalsutra' and asked about his father.

After the meeting, the family was forced to wait for their car outside the Pakistan Foreign Office, leaving them exposed to harassment by the Pakistani media. They were bombarded with questions like – "Aapke husband ne hazaaron begunah Pakistaniyon ke khoon se Holi kheli. Ispar kya kahengi? (Your husband killed thousands of innocent Pakistanis. What do you have to say about that?)'" and "Aapke kya jazbaat hain apne kaatil bete se milne ke baad? (How do you feel after meeting your killer son?)".

Pakistan probably thinks that by allowing a meeting with the family, it has diluted India's primary claim in the ICJ. But the fact is that by subjecting Jadhav's family members to such inhuman treatment, Pakistan has foiled its own attempts to come across as humane and just.

Such diplomatic face-offs with Pakistan are not new to India. Famously in 1992, a counsellor-level official in the Indian Mission Rajesh Mittal was abducted in Islamabad. Unlike Jadhav, Mittal enjoyed diplomatic immunity. But Pakistan again countermanded the Vienna convention by torturing Mittal.

India should make more efforts at the international level in Jadhav's case. It should not be seen as the question of one individual but as a matter of credibility for India as a responsible and a peace-loving state. With this case, Pakistan is trying to convince the world that its neighbour India is responsible for all the mess within its boundaries and Indian agencies are involved in organising terrorist attacks and creating instability in Balochistan. India should counter this propaganda with full force by exposing Pakistan in the case of Jadhav and showing the world how this country is blatantly funding terrorists in Kashmir on one hand and committing human rights violations in its own territories on the other. ■

(Author is Assistant Professor in Satyawati College, Delhi University)

असमः अभाविप द्वारा छात्र नेता कार्यशाला आयोजित

अभाविप असम प्रदेश द्वारा दो दिवसीय छात्र नेता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्र नेता उपस्थित थे। कार्यशाला का आयोजन असम के होजाई स्थित गीताश्रम में किया गया था। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री रोहित मिश्रा ने कहा कि हम युवा हैं, युवाओं के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। हमें अपना दायित्व ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए। वहीं अभाविप असम के प्रदेश अध्यक्ष शैलेन गगै ने उपस्थित छात्र नेताओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्श मूल्यों को आत्मसात कर कार्य करने की बात कही।

द्वितीय सत्र में अभाविप के अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख श्रीहरि बोरिकर ने अपने संबोधन में कहा कि 'एनआरसी' का काम तीव्र गति से चल रहा है, जिसे वामपंथी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को सर्वप्रथम 1972 में विद्यार्थी परिषद् ने ही उठाया। उन्होंने कहा कि 1982 में प्रफुल्ल मंहत (जो बाद में असम के मुख्यमंत्री भी बने) ने विद्यार्थी परिषद् के साथ मिलकर बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन चलाया था। सत्र के बाद रात में सास्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद् के कार्यकर्ताओं ने बढ़ - चढ़कर भाग लिया।

दूसरे दिन के प्रथम सत्र में क्षेत्रीय संगठन मंत्री नीरव घेलानी ने परिषद् के विचारों के परिसर में ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरी है। दूसरे सत्र में गटशः चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग संगठन मंत्री, जिला संगठन मंत्री एवं जिला संयोजक उपस्थित थे। कार्यशाला के संवर्धना सत्र में होजाई जिला के उपायुक्त भी उपस्थित थे, उपायुक्त ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद् एक अनूठा छात्र संगठन है, यही वो संगठन है जो हमेशा ज्ञान, शील और एकता के साथ छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करती है। छात्रों को अपने पढ़ाई के साथ-साथ परिषद् से जुड़कर समाज जीवन में अपना हाथ बंटाना चाहिए।

कार्यशाला में अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री सीमांत दास, प्रदेश मंत्री नयनज्योति शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री अपांशु शेखर शील समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के लगभग 400 छात्र नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ■

Analysis India's vote in UN favour of Palestine

Pavan Chaurasia

Noted journalist Fareed Zakaria, in his book The Post-American World has argued that, "...foreign policy is a matter of costs and benefits, not theology." Nations do not go by emotions but rather are driven by realpolitik. It is true for all the nations of the world and India is no exception to it. The recent case of India voting in favour of the UN resolution criticizing the USA for its recognition of Jerusalem as Israel's capital has raised several questions as well as certain outrage in social media by the supporters of the government who had expected that India under Modi government would shun its traditional Nehruvian policy and would either vote against the resolution or abstain from voting. There expectations were not totally unfounded because the relations between India and Israel are at all time high due to the personal efforts of Prime Minister Modi. This voting has also come at a time when Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is set to visit India very soon. The Indian stand was criticized by ruling party MPs including Subramaniyan Swami and Swapan Das Gupta too. But this 'strange' decision of India needs to be properly analysed before jumping to any conclusion.

Trump's declaration and the subsequent UN resolution

On 6th December, US President Donald Trump, fulfilling his election campaign promise, announced the officially recognition of Jerusalem as the capital of Israel decided to move the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem. This move created massive uproar and several countries criticized the move. However, Trump isn't the only US President to declare his intentions to move the U.S. embassy; both former Presidents Bill Clinton and George W. Bush had also pledged to move the embassy. The US Congress in 1995 approved the funding and relocation of the embassy to Jerusalem by 1999. But the law included a stipulation, allowing for presidents to sign continuous waivers to stall the relocation of the embassy. Every President since used the waiver in an effort to avoid conflict with the peace negotiations. To counter this US move, Egypt drafted a resolution which avoided mentioning the U.S. by name. After the veto in the Security Council, Egypt and Turkey brought the matter to an emergency session of the UN General Assembly. The resolution, co-sponsored by Turkey and Yemen, called Trump's recognition "null and void" and reaffirmed 10 Security Council resolutions on Jerusalem dating back to 1967, including requirements that the city's final status must be decided in direct negotiations between Israel and the Palestinians. It also demanded that "all states comply with Security Council resolutions regarding the holy city of Jerusalem and not to recognise any actions or measures contrary to those resolutions". Major political powers such as Britain, France, Germany and Japan voted for the resolution. India, along with China, Nepal, Pakistan and other neighbours (except Bhutan) too voted for the resolution. The nine countries that voted a "No" were the US, Israel, Guatemala, Honduras, Micronesia, Nauru, Palau, the Marshall Islands and Togo. Among the abstentions were Australia, Argentina, Canada, Colombia, Croatia, Czech Republic and Mexico. The absent countries included Kenya, Georgia and Ukraine, all of which have close US ties. Trump had threatened to cut funding to the countries that did not back the US recognition. Israel's

Prime Minister Benjamin Netanyahu has completely rejected the UN resolution and reiterated that Jerusalem always was, always will be Israel's capital. He also appreciated and thanked President Trump for his "stalwart defense of Israel."

Modern History of Jerusalem

Jerusalem, the historic capital of biblical Israel, houses holy places of all three Abrahamic religions and is claimed by both Israelis and Palestinians. It is the third holiest place in Islam after Mecca and Medina. The city is also closely linked to Christianity. For the Jews, Jerusalem was the home of their two ancient temples, both being destroyed by invading armies; the first by the Babylonian ruler Nebuchadnezzar II in 586 BCE and the second by the Romans in 70 CE. Hence, Jerusalem is the holiest place for the Jews too. The present day controversy over Jerusalem dates back to Israeli Declaration of Independence which announced the establishment of Israel in 1948. The declaration was however, conspicuously silent on the country's capital because a formal declaration of Jerusalem as the capital would have antagonizes many including the US, whose recognition was critical for the Jewish State. The city was also not a part of Israel in the original 1947 UN plan to partition Palestine. Jerusalem was supposed to be ruled by an international trusteeship. However, the UN-sponsored Armistice Agreement between Israel and Jordan in 1949 formalized the division of Jerusalem. West Jerusalem was to be controlled by Israel and the East by Jordan, including the old city and its religious sites holy to all the three Abrahamic faiths. Israeli Jews weren't allowed to pray in the area while Jordan controlled it. In the same year, Israel declared the Western Jerusalem as its capital and gradually established or moved all its sovereign institutions. However, foreign governments largely avoided Jerusalem and opened embassies in Tel Aviv, in recognition of the United Nations resolution. The eastern part was subsequently conquered by Israel in the 1967 Arab-Israel War. The UN Security Council Resolution 478 of 1980 condemned Israel's decision to annex East Jerusalem as a violation of international law and called for a compromise solution. In 1980 Israel passed a bill that declared "Jerusalem, complete and united, is the capital of Israel" — although it stopped short of annexing East Jerusalem, a move that would most likely have drawn international outrage. The 1993 Oslo accords deferred from a resolution on core issues: borders, refugees and Jerusalem's status.

India and Jerusalem

Although India recognized Israel in 1950 but did not initiate diplomatic relations and it was only in 1992 that India opened its embassy in Tel Aviv. India has long maintained that Jerusalem must be a part of "permanent status negotiations" of issues left untouched by the Oslo Accords of 1993 and has argued for two-state solution. For nearly a decade India's support for a Palestinian state was accompanied by an explicit reference to East Jerusalem being the Palestinian capital. However, in recent months, there was a considerable change in the formulation of Indian statements on the Palestine problem, as the phrase 'East Jerusalem' was absent from it. This gave rise to a doubt about India's vote in the General Assembly. Before the voting the Ministry of External Affairs (MEA) had said that India's position on Palestine is independent and consistent and was shaped by its views and interests, and not determined by any third country and therefore the Indian stand in UN was in sync with it, as despite having excellent relations with US and Israel,

it did not subvert its own interest. Trade with the Arab world, Chinese influence in West Asia and its own pragmatism were perhaps the major considerations that lead to India voting in favour of resolution. India has been cementing its ties with the Gulf Cooperation Council (GCC) nations which house around 70 per cent of NRIs with annual remittance of around $40 billion and is a major source for its energy requirements. The rich GCC nations are also a tempting option to further PM Modi's ambition to make India the number one investment destination. By voting against the resolution, India did not wanted to antagonize the entire Muslim world and thereby threatening its energy security as well as massive diaspora and remittance obtained from the region.

An increasingly domineering China too has played a massive role in shaping up the Indian policy in West Asia. China has fully supported the Palestinian theory of two-state solution with its capital in East Jerusalem. Therefore India did not wanted to be on the losing side as majority of third world countries were in favour of the resolution. It would have also given a 'natural' advantage to China over India. The government, no doubt, must have analysed the cost-benefit ratio that India's vote would disappoint Israel and the US. But it must have perhaps understood that the resolution is non-binding in nature and would hardly change the ground realities as well as Trump's position and is more of a symbolic gesture. Therefore, the larger message that New Delhi wanted to give is that India has dehyphenated its relations with Israel from its position on Palestine. ■

(Writer is Research Scholar in JNU)

छत्तीसगढ़ अभाविप द्वारा प्रांत छात्रा अभ्यास वर्ग आयोजित

अभाविप, छत्तीसगढ़ द्वारा दो दिवसीय प्रांत छात्रा अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तीकरण, सूरक्षा, शिक्षा, स्वास्थय आदि विषयों पर गहन चिंतन किया गया। वर्ग में राष्ट्र के प्रति महिलाओं के योगदान पर चर्चा व वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं को प्राप्त होने वाले अवसर एवं संभवनाओं पर विशेष जोर दिया गया।

समानांतर सत्रों के माध्यम से छात्राओं में नेतृत्व विकास, मीडिया प्रशिक्षण, भाषण कला, गीत आदि का प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर छात्रा प्रतिनिधियों द्वारा वीरांगनाओं की वीर गाथाओं की व्याख्या की गई एवं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाओं के पद चिह्नों पर संकल्प लिया। वर्ग में छत्तीसगढ़ प्रांत के सभी विभागों की अलग-अलग बैठक कर समस्याओं पर चर्चा कर योजनाएं बनाई गई तथा राष्ट्रव्यापी समस्याओं पर चिंतन कर केरल में हो रहे राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्तियों की हत्याओं पर रोष व्यक्त करते हुए इस

समस्या के निदान में अपनी भूमिका निश्चित करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में मध्य क्षेत्र के सह संगठन मंत्री चेतस भाई सुखाड़िया, प्रांत संगठन मंत्री मधुसूदन जोशी, धर्मतरी महापौर अर्चना चौबे, प्रांत छात्रा प्रमुख डिंपल बिनदेकर, प्रांत सह छात्रा प्रमुख विभा अवस्थी सहित सैंकड़ों अभाविप कार्यकर्ता मौजूद थे। ■

बंगाल में बढ़ती महिला हिंसा के खिलाफ अभाविप का प्रदर्शन

16 दिसंबर को देश भर में लोगों ने नम आंखों से निर्भया को याद किया। निर्भया कांड के आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई गई, लेकिन एक निर्भया ऐसी भी है जिनकी आत्मा आज भी कराह रही है। बोलपुर के 20 वर्षीय निर्भया की.. जिसकी आवाज न सरकार को सुनाई दी और न ही बुद्धिजीवियों को.... बोलपुर की निर्भया के लिए इंडिया गेट पर कोई कैंडिल मार्च नहीं निकाला गया और न ही किसी मीडिया के द्वारा प्रमुखता से उठाया गया। इस 20 वर्षीय निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए अभाविप लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस क्रम में कोलकाता में अभाविप द्वारा कैंडिल मार्च निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान अभाविप कार्यकर्ता, लगातार आरोपी शेख हाफिजुल को फांसी देने की मांग कर रहे थे।

सभा को संबोधित करते हुए परिषद् के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजस्थान में कोई घटना घटती है तो बंगाल में कैंडिल मार्च निकाला जाता है, लेकिन जब बंगाल में एक मासूम बच्ची का बलात्कार कर आत्महत्या के लये मजबूर किया जाता है तो प्रशासन अँधा बन जाता है। यहां की मुख्यमंत्री को देश भर में हो रहे घटनाओं पर चिंता है परंतु अपने गृह राज्य में हो रहे महिला हिंसा दिखाई नहीं देती। बोलपुर के निर्धन परिवार की रहने वाली 20 वर्षीय युवती को सरकार की गीताजंली आवास योजना के कर्मचारी शेख हाफिजल द्वारा ब्लैकमेल कर लगातार दुष्कर्म किया गया। लगातार दुष्कर्म और ब्लैकमेल से परेशान होकर युवती आत्महत्या कर लेती है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार का सुध लेना उचित नहीं समझा गया है। जबकि राजस्थान के एक घटना में मरने वाले मालदा के अफराजुल खान के परिवार को तृणमूल सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान की है। इससे साफ है कि ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में संलिप्त है। बोलपुर घटना के आरोपी के खिलाफ सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना तुष्टीकरण राजनीति को प्रमाणित करती है। ■

क्या है मामला?

पश्चिम बंगाल के बोलपुर (कोलकाता) के बाहरी इलाके स्थित रजतपुर गांव में सरकार के द्वारा चलाये जा रहे गीतांजली आवास योजना के कर्मचारी शेख हाफिजुल ने अपने मोबाईल से स्नान करती एक १० वर्षीय युवती का आपत्तीजनक तस्वीर खींच ली। तस्वीर को सार्वजनिक करने की धमकी देकर हाफिजुल ने युवती को बोलपुर स्थित डेयर पार्क बुलाया, जहां जबरन उसके साथ बलात्कार किया गया। यह सिलसिला लगातार जारी रहा, युवती लोकलाज के भय से चुप रही। जब स्थिति बर्दाश्त के बाहर हो गई तो युवती ने परेशान होकर लगा ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस निर्भया को इंसाफ मिल पायेगा?

गौरतलब है कि हाल के दिनों में पंश्चिम बंगाल में महिला हिंसाचार, लुट, हत्या, मारपीट की घटना लगातार बढ़ी है। बंगाल सरकार इस पर लगाम लगाने में असफल रही है। अभाविप का कहना है सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है।

विद्या ददाति विनयम्

| अजीत कुमार सिंह |

विद्या ददाति विनयम - विनयाद् याति पात्रताम ।
पात्रत्वाद् धनमाप्नोती - धनाद् धर्मस्ततः सुखम्।।

अर्थात विद्या से विनय - विनय से योग्यता - योग्यता से धन - धन से धर्म एवं धर्म के पालन से सुख की प्राप्ति होती है। भारतीय ऋषि मुनियों के अनुसार विद्या प्राप्ति का उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान को हासिल करना नहीं बल्कि अपने अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना है। विद्या विनय देती हैं, विनय से व्यक्तित्व यानि पात्रता का विकास होता है और पात्रता के माध्यम से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। विद्या प्राप्ति का अर्थ सिर्फ ऊंची-ऊंची डिग्रीयां हासिल करना नहीं है। विद्या प्राप्ति का सही अर्थ आपके अंदर विनय यानि शील हो, परंतु आजकल देखा जा रहा है कि कि पढ़े लिखे लोगों में विवेक का अभाव होने के कारण विनय का प्रादुर्भाव होने के स्थान पर अहंकार की उत्पत्ति हो रही है। जो कि चिंता का विषय है।

वर्तमान में जिसे लोग विद्या कहते हैं वह विद्या न होकर सूचना का माध्यम बन चुका है। सूचनाएं पुस्तकों एवं संवाद के माध्यम से प्राप्त हो जाती है लेकिन विवेक का प्रकाश तो हमारे अंतर्निहित है, जिसे हमें स्वयं जागृत करना पड़ता है। विवेक की ज्योति किसी पुस्तकालय या कोचिंग संस्थानों में नहीं मिलती, विवेक अच्छे संस्कारों से उत्पन्न होता है। विवेक की पहली किरण अपने माता - पिता से प्राप्त होती है। मुनष्य जीवन में अच्छे संस्कारों का बहुत महत्व है। हमारी सनातन जीवन पद्धति दैनिक जीवन संस्कार पर आधारित है, यह जीवन पद्धति पूरे विश्व में सबसे अनूठी जीवन पद्धति है।

श्रीमद्भागवत ने भी तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भी ऊपर पंचम पुरूषार्थ की घोषणा कर दी थी - *"प्रेमः पुमर्थो महान"।*

यह प्रेम, यह भक्ति अर्थात सघन अनुभूति जब साधना, साक्षात्कार के साथ मिलेगी तभी विद्या का वास्तविक अर्थ अपने आपको प्रकट करेगा। तभी हृदय विशाल होगा, तभी ऊंचे आदर्शों के प्रति हमारी रूचि बढ़ेगी, तभी हम उनके प्रति प्रतिबद्ध होंगे, तभी हम उनके प्रति शिथिल होंगे, हम जीवनमुक्त बन सकेंगे। तभी हमें संपूर्ण संसार, अपना

लगने लगेगा, तभी हम संपूर्ण होंगे। विद्या ही तो पूर्णता देती है। ऐसा पहले भी हुआ है, अब भी हो सकता है, आगे भी होगा। अगर हम इतिहास के पूरे कालखंड पर यदि दृष्टिपात करेंगे तो ऐसे जीवन्मुक्तों की अविरल परंपरा का दर्शन हम कर सकेंगे। यही मुक्तिदायिनी विद्या है।

इस विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती है। शुभ्र धवलवसना मां शारदा वीणा पुस्तकधारिणी है संगीत और साहित्य दोनो ही वाङ्देवी को अलंकृत करते हैं। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा बंसत पंचमी को की जाती है, जिसका शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। बसंत ऋतु में फूलों की खूशबू से वातावरण सुंगधित हो उठता है। गेहूं की बालियां सोने के समान खिलने लगती है, आमों में बौर आ जाती है और हर तरफ तितलियां मंडराने लगती है। मनुष्य तो मनुष्य, पक्षी भी उल्लास से विभोर हो उठते हैं। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है, चूंकि इस मौसम न अधिक गर्मी होती है और न सर्दी। मां शारदा की अराधना कर हम भी अपने जीवन में बसंत के समान खिलखिला सकते हैं। मां शारदे की अराधना हम सभी के लिए विशेष फलदायी है। बसंत पंचमी को मां शारदे के जन्मदिन के रूप में माना जाता है, इसलिए इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शील, विवेक, चातुर्य प्राप्त करने की कामना की जाती है।

मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वी पर एक अद्भूत चतुर्भुजी शक्ति का अवतार हुआ, जिसके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वरदान मुद्रा में था। वहीं अन्य दो हाथों में किताब एवं माला थी। वीणापाणी देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव-जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई, उसी दिन भगवान ब्रह्मा ने उनका नामांकरण सरस्वती के रूप में किया। माता सरस्वती को शारदा, वीणापाणी, कमलवासिनी, बागीश्वरी, भगवती आदि नामों से पूजा जाता है। संगीत उत्पत्ति करने के कारण उन्हें संगीत की देवी भी कहते हैं। विद्या के बिना सब बेकार है, तभी तो हमारे शास्त्रों में विद्या का स्थान सबसे ऊपर माना गया है -

रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा।
विद्या हीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किन्शुकाः।।

यानि रूप-यौवन से संपन्न हों, विशाल कुल में जन्म भी लिया हो लेकिन आप विद्या विहीन हैं यानि ज्ञान हीन हैं तो आप उस पलास के फूल के समान हैं जो सुन्दर होते हुए भी सुगंधहीन और शोभित है। बिना सुगंध के पुष्पों को देवता भी स्वीकार नहीं करते और न भक्त अपने भगवान पर चढ़ाते हैं। कितना भी सुंदर, सुडौल शरीर हो, विद्या के बिना सब बेकार है। विद्या के समान कोई धन नहीं है। किसी धनी व्यक्ति को गरीब होते हुए आपने सुना होगा। लेकिन किसी विद्वान व्यक्ति को निरक्षर होते नहीं देखा होगा। विद्या की प्राप्ती तप से होती है, बिना तपस्वी बने विद्या की कल्पना नहीं की जा सकती है। विद्या के बिना मनुष्य को पशु से भी बदतर समझा जाता है।

न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा।
विवेक हीना पशुभिः समाना।।

दिव्य-चक्षु की चर्चा शास्त्रों में सदैव की गई है। यह दिव्य चक्षु क्या है? यह दिव्य चक्षु विद्या यानि ज्ञान ही तो है। ज्ञान के बिना व्यक्ति आंख रहते हुए भी अंधा है, कान रहते हुए भी बहरा है। संसार के विराट वैभव का दर्शन इस भौतिक आंख से संभव नहीं है, ब्रह्माण्ड के सूक्ष्म तत्त्व का दर्शन दिव्य आंख से ही संभव है, यह आंख विद्या ही तो है जो विनय से प्राप्त होती है। विवेक रहित विद्या का परिणाम क्षोभ जनक सुख ही होता है।

को हि भारः समर्थानां किं दूर व्यवसायिनाम्।
को विदेश सुविद्यानां को परः प्रियवादिनम्।।

सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई वस्तु भारी नहीं होती। व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती। विद्वान के लिए कहीं विदेश नहीं होता। मधुर बोलने वाले का कोई पराया नहीं होता इसलिए हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए।

विद्या की महत्ता को निम्न श्लोक से सहज आंका जा सकता है -

येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः।
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति।।

जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया, न ही उसने व्रत और तप किया, थोड़ा बहुत अन्न-वस्त्र-धन या विद्या दान नहीं दिया, न उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है। ऐसे मनुष्य इस धरती पर भार होते हैं। मनुष्य रूप में होते हुए भी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं।

बसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वी पर एक अद्भूत चतुर्भुजी शक्ति का अवतार हुआ, जिसके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दो हाथों में किताब एवं माला थी। वीणापाणी देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव - जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई, उसी दिन भगवान ब्रह्मा ने उनका नामांकरण सरस्वती के रूप में किया। माता सरस्वती को शारदा, वीणापाणी, कमलवासिनी, बागीश्वरी, भगवती आदि नामों से पूजा की जाती है। संगीत की उत्पति करने के कारण उन्हें संगीत की देवी भी कहते हैं।

विद्या मनुष्य के सभी इच्छाओं का अंत कर देती है, उसे सुख-दुःखादि के द्वंदों के अतीत से ऊपर उठा देती है। यह विद्या मनुष्य के सभी भयों, सभी बंधनों, सभी कुंठाओं, सभी मर्यादाओं, सीमाओं की परिधि के पार ले जाती है। विद्या की अधिष्ठाती मां सरस्वती से यही वर मांगते हैं कि इस बसंत में हम सभी के ज्ञान चक्षु एवं हृदयों को सामरस्य गान से निरंतर झंकृत करती रहे, ताकि भारत के पुनर्वैभव फिर से स्थापित हो सके। ममता और ज्ञान की झंकार से भारत एक बार फिर विश्व गुरू बनकर पूरे विश्व में बंधुत्व की भावना स्थापित कर समस्त संसार को एक सूत्र में बांध सके। ■

निष्पक्षता ही पत्रकारिता की पहचान : प्रभु चावला

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, दीनदयाल उपाध्याय मानव अध्ययन शोध पीठ और छात्र कल्याण न्यास की ओर से कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर में आयोजित दो दिवसीय मीडिया कार्यशाला में वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने कहा कि खबर की पूरी सच्चाई को जानकर और हर पहलू का विश्वलेषण करके प्रकाशित की गई खबर ही पत्रकार को पहचान दिलाती है। खबर में अपने विचारों को स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। निष्पक्षता ही पत्रकार की पहचान होती है।

वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने ने कहा कि पत्रकारों को दीनदयाल से सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने निर्भीक और निष्पक्षता से ही अपनी पहचान बनाई थी। पत्रकारिता की भी एक लक्ष्मण रेखा होती है। उस रेखा को मानते हुए राष्ट्र हित में पत्रकारिता करने की आवश्यकता है। वहीं अभाविप के अखिल भारतीय जनजाति कार्य प्रमुख व क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने कहा कि युवा वर्ग को सकारात्मक दृष्टिकोण से राष्ट्रहित में कार्य करने की आवश्यकता है। मीडिया को सनसनी खबर छापने के बजाय तथ्यपरक खबरों पर ध्यान देना चाहिए।

अभाविप के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक साकेत बहुगुणा ने कहा कि भारत को स्वदेशी मूल्यों और दृष्टि के साथ आगे बढ़ना है। छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने देशभर में युवाओं का ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका में राष्ट्रवादी विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति डॉ. एमएस परमार ने कहा कि पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सही अर्थ समझने होंगे। इतिहास और संविधान की बेहतर समझ रखने वाले पत्रकार ही अपने प्रोफेशन से साथ सही न्याय कर सकते हैं। डॉ. परमार ने मेडिकल और बार काउन्सिल ऑफ इंडिया की तरह मीडिया काउन्सिल गठन करने की वकालत की।

मीडिया कार्यशाला के दूसरे दिन ज्वलंत विषयों पर चर्चा हुई। इसमें महिला अस्मिता और विज्ञापन में मीडिया की भूमिका पर प्रियंका कौशल और आशा शुक्ला ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में छात्रों को बताया कि पत्रकारिता राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सकारात्मक भूमिका अदा कर सकती है।

टीवी पत्रकार अनुराधा प्रसाद ने कहा कि तकनीकी ने पत्रकारिता का चेहरा बदल दिया है। इसके कारण पत्रकारिता की जिम्मेवारी और भूमिका बदल गई। अब परंपरागत पत्रकारिता के बीच रास्ते निकालने की जरूरत है, ताकि लोकतंत्र का जो भरोसा पत्रकारिता पर बना है वह और मजबूत हो सके। ■

नई शिक्षा नीति में और कितनी देर....?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति द्वारा नई शिक्षा नीति तैयार की जा रही है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय बहुत दिनों से एक समिति बनाने की तैयारी में लगा हुआ था और 2017 के अंत तक नई नीति का प्रारूप जारी होने की बात कही गयी थी। इसके पहले पूर्व कैबिनेट सचिव टीआर सुब्रमण्यम के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए एक समिति का गठन हुआ था, देशव्यापी विमर्श के बाद इस समिति ने अपनी 200 पन्नों की रिपोर्ट जून 2017 में जमा कर दी। लेकिन बाद में एचआरडी मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को शिक्षा नीति का प्रारूप मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा नई कमेटी बनाने की बात हो रही थी। 2018 आ गया लेकिन अभी तक शिक्षा नीति का मसौदा नही आया। आख़िरकार नई शिक्षा नीति तैयार करने में हो रही देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? नई शिक्षा नीति पर "राष्ट्रीय छात्रशक्ति" के संवाददाता श्री उत्कर्ष श्रीवास्तव ने इस विषय पर देशभर के छात्रों से चर्चा की जो निम्न हैं–

नई शिक्षा नीतियों में जिन मूल्यों, नैतिकता और जीवन मूल्यों को शामिल किया जाएगा उसमें वैज्ञानिकता का समावेश होना भी जरुरी है। नई शिक्षा नीति किन–किन बिंदुओं पर प्रहार करने वाली है इसका अंदाजा लगाना कठिन है, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द एक सकारात्मक परिवर्तन आगामी शिक्षा नीति के माध्यम से होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित किये जाने की जरुरत है। और इसके साथ ही शिक्षा के अधिकार कानून को मजबूती प्रदान करवाना होगा।

सौरभ त्रिवेदी, सैम हिग्गिनबाटम यूनिवर्सिटी ऑफ़ ऐग्रिकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज,इलाहाबाद

नई शिक्षा नीति से देश में क्रांति आएगी इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ब्लाक, तहसील, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने के पश्चात इसे तैयार किया जा रहा है इसलिए इसमें समय लगना स्वाभाविक है। देशभर के शिक्षाविदों के मार्गदर्शन में तैयार की जा रही शिक्षा नीति केवल विद्यालय की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं होगी।

मनीष सिंह मालिक, राजस्थान विश्वविद्याल

प्रारंभ में नरेन्द्र मोदी की सरकार ने जो उत्साह दिखाया था वो धीरे-धीरे ख़त्म होता जा रहा है। नई शिक्षा नीति को लागू करना तो दूर की बात लग रही है। परन्तु शिक्षा नीति को लेकर जो चर्चायें सुनाई दे रहीं हैं उससे सकारात्मक कदम माना जा सकता है। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश हेतु बढ़ावा देना और शिक्षण के माध्यम की भाषा के रूप में मातृभाषा का प्रयोग करके क्षेत्रीय व स्थानीय भाषा के महत्त्व को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नई शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

बबली सिंह, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

शिक्षा व्यवस्था पर नजर डाले तों प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की स्थिति इतनी ख़राब है कि लोग अपने बच्चों को बिना ट्यूशन और कोचिंग के पढ़ा ही नही रहे हैं। किसी देश का भविष्य वहां के बच्चों को मिलने वाली प्राथमिक शिक्षा पर निर्भर करता है। प्रारम्भिक शिक्षा जिस प्रकार की होगी देश का भविष्य भी उसी प्रकार निर्धारित होगा। शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है और इसमें सुधार करने के लिए कोई ठोस कदम नही उठाये जा रहे हैं।

गौरव कुमार मिश्र, शुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ

मंत्रालय ने विभिन्न विशेषज्ञता और शैक्षणिक योग्यता वाली पृष्ठभूमि के लोगों को इस समिति में शामिल किया है। मंत्रालय का मानना है कि यह समिति भारतीय शिक्षा नीति को नये सिरे से गढ़ने का काम करेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह हैं कि जब इसके पहले एक समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है तो फिर से नई समिति बनाने का क्या औचित्य है?

फरमान हैदर, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी

राज्यों में शिक्षक भर्ती आयोग का गठन, GDP का 6% शिक्षा पर खर्च, नो डिटेंशन कक्षा 8 से घटाकर कक्षा 05 तक होगा तथा इस प्रकार के अन्य कई परिवर्तनों की बात नई शिक्षा नीति में की जा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने हेतु नई शिक्षा को और प्रभावशाली बनाया जाना आवश्यक है। इसलिए निश्चित समय के भीतर इसे लागू करने का प्रयास होना चाहिए।

राम प्रकाश यादव, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

छात्रसंघ चुनाव

झारखंड के कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में नव निर्वाचित छात्र नेता के साथ अभाविप पदाधिकारी

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी छात्रसंघ में जीत हासिल करने के बाद
विजय जुलूस निकालते अभाविप कार्यकर्ता

RNI No.: DELBIL/2017/73636
Date of Posting: 10-11 January, 2018
Date of Publishing: 8 January, 2018

Postal Regd. No.: DL(C)-11/1409/2017-2019
Post Office: NDGPO, New Delhi

विदर्भ प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन करते केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर व अन्य अभाविप पदाधिकारी

राजस्थान के प्रांतीय अधिवेशन के दौरान शहर में निकलती भव्य शोभा यात्रा